

Publication : Hindustan  
Date : Friday, February 05, 2010  
Edition : New Delhi  
Page : Front

# पचौरी के साथ राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र

केंद्र सरकार ने परोक्ष रूप से माना अन्तरराष्ट्रीय लॉबी के निशाने पर हैं पचौरी

मदन जैड़ा  
नई दिल्ली

जलवायु परिवर्तन पर विकसित देशों को आईना दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय लॉबी के निशाने पर आए डॉ. आर.के. पचौरी के साथ देश और देशों की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र आ गई है।

भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट पैनल ने आईपीसीसी के चैयरमैन पचौरी का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि रिपोर्ट में हुई गलतियों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि वे पूरी तरह से पचौरी के साथ हैं। पचौरी ने अभी कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था

कि अन्तरराष्ट्रीय लॉबी इस रिपोर्ट के बहाने उन्हें और आईपीसीसी को निशाना बना रही है। पचौरी के नेतृत्व में दिल्ली में शुक्रवार से जलवायु परिवर्तन पर शुरू हो रहे अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन से ठीक पूर्व सरकार और यूएन के रुख को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

दो दिन पूर्व ही हिन्दुस्तान को दिए बयान में पचौरी ने अमेरिका के सेंटर फॉर पब्लिक इंटीग्रिटी की रिपोर्ट का जिक्र कर कहा था। उन्होंने बताया था कि 770 बड़ी कंपनियों ने 2340 लॉबियों को जलवायु परिवर्तन की नीतियों से भटकाने के काम पर लगाया हुआ है।

अमेरिका में हर सांसद के पीछे ऐसी चार लॉबियां काम कर रही हैं। ये लॉबियां अब विश्व के दूसरे हिस्सों में भी सक्रिय हो गई हैं। अब इनके निशाने



■ आर.के. पचौरी - लॉबी के निशाने पर

## सरकार ने दिया समर्थन

- आईपीसीसी को पांचवी एसेसमेंट रिपोर्ट के लिए वैज्ञानिक सहायता
- संरा में कार्यकारी सचिव दि बोअर ने कहा, आंधी से लड़ रहे हैं पचौरी

पर आईपीसीसी और इसके चैयरमैन के रूप में वह भी हैं, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया को आगाह कर रहे हैं। सरकारों को नीतियां बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

इस मुद्दे पर वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा, 'पचौरी को भारत

सरकार का सौ फीसदी समर्थन प्राप्त है। पचौरी का आईपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में मैं और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह भी सौ फीसदी समर्थन करते हैं।' रमेश ने कहा कि आईपीसीसी की पांचवीं एसेसमेंट रिपोर्ट 2014 में आएगी।

सरकार ने इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन की सिफारिश की है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, केंद्र ने उन्हें वैज्ञानिक मदद की भी पेशकश की है जिससे पचौरी सहमत हैं।

उधर, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव यवो दि बोअर ने कहा कि आईपीसीसी रिपोर्ट की गलतियों के लिए पचौरी को जिम्मेदार ठहराना या उनके इस्तीफे की मांग करना गलत है। गलती को सुधारा जा चुका है, इसलिए यह विवाद अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा पचौरी तो बड़े पेड़ की तरह हैं जो आंधी का सामना कर रहे हैं।